भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1908

मंगलवार, 11 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

बेंचमार्क मूल्य-निर्धारण नीति

1908. श्री राजमोहन उन्नीथनः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा उद्योग में स्वीकार्य मूल्य-निर्धारण दरों को मानकीकृत करने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं, जहां विभिन्न ऑपरेटर अलग-अलग मूल्य वसूल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने लॉजिस्टिक्स उद्योग के लिए बेंचमार्क मूल्य निर्धारण नीतियों का पता लगाने के प्रस्ताव पर विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है और इसका ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ङ): मूल्य निर्धारण बाजार से निर्धारित होने वाली प्रक्रिया है और सरकार इस पर नियंत्रण नहीं रखती। हालांकि, लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार और लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के लिए, 17 सितंबर, 2022 को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (एनएलपी) शुरू की गई थी। एनएलपी का एक उद्देश्य भारत में लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना है, ताकि देश वैश्विक मानकों के अनुसार प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो सके। इस संबंध में सरकार द्वारा कई उपाय किए गए हैं, जिनमें भौतिक और डिजिटल अवसंरचना का विकास शामिल है, जैसे यूनीफाइड लॉजिस्टिक्स इंटीग्रेटेड प्लेटफ़ॉर्म (यूएलआईपी), लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक (एलडीबी), लॉजिस्टिक्स उपयोगकर्ता के मामलों के समय पर समाधान के लिए एक डिजिटल पोर्टल (ई-एलओजीएस), एनएलपी-मरीन, आदि।

*****